100

उत्तराखण्ड शासन चिकित्सा अनुभाग–4

संख्या- /XXVIII-4-2013-22/2008 देहरादून : दिनांक 11 अक्टूबर, 2013

कार्यालय ज्ञाप

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अनुपालन में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार कल्याण सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाये जाने हेतु राज्य स्तर पर "राज्य क्वालिटी एश्यूरेन्स कमेटी" का गठन शासनादेश संख्या—117/XXVIII-4-2008-22/2008 दिनांक 17.06.2008 द्वारा किया गया था ।

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या N.23011/68/2011—(Policy)(Pt). दिनांक 13.02.2013 द्वारा उक्त कमेटी के गठन के संबंध में निर्गत नवीनतम निर्देशों के अनुपालन में प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर "राज्य क्वालिटी एश्यूरेन्स कमेटी" का पुर्नगठन निम्नवत् किया जाता है:—

1.	प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0 कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।	अध्यक्ष (पदेन)
2.	महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड (संयोजक)।	सदस्य (पर्दन)
3.	निदेशक, चिकित्सा उपचार।	सदस्य
4.	डा० मीनाक्षी जोशी (स्त्री रोग विशेषज्ञ, दून महिला चिकित्सालय, देहरादून)	सदस्य
5.	डा० महेश भट्ट (वाईसेक्टामी शल्यक दून चिकित्सालय, देहरादून)	सदस्य
6.	डा०राकेश बलूनी (ऐनेस्थेटिस्ट, दून चिकित्सालय, देहरादून)	सदस्य
7.	राज्य नर्सिग सलाहकार (सचिव, उत्तराखण्ड राज्य चिकित्सा संकाय)	सदस्य (पदेन)
8.	संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण।	सदस्य (पदेन)
9.	डा० संदीप आहूजा, जन कल्याण चिकित्सालय एवं अनुसंधान संस्थान, 4 ओल्ड सर्वे रोड, देहरादून (एकीडीटेड निजी संस्थान से)	सदस्य
10.	श्री सुशील पुरोहित (विधि सलाहकार, राज्य पी.सी.एण्ड पी.एन.डी.टी. सेल)	सदस्य

उक्त समिति भारत सरकार द्वारा जारी दिशा—निर्देशों के अनुसार कार्य करेगी, जिसके उददेश्य एवं कार्य निम्नवत् होंगे :—

 परिवार नियोजन सेवा प्रदान करने वाले निजी और सार्वजिनक संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय मानकों के क्रियान्वयन किया जा रहा है अथवा नहीं, की जानकारी हेतु संस्थानों का भ्रमण करना।

- 2. नसबन्दी आपरेशन के दौरान/उपरान्त होने वाली मृत्यु/जटिलताओं की समीक्षा एवं सूचना तैयार करना।
- 3. नसबन्दी आपरेशन के असफलता के कारणों की समीक्षा एवं सूचना तैयार करना।
- 4. राज्य में परिवार कल्याण कार्यक्रमों जैसे नसबन्दी आपरेशन सेवा इत्यादि की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु आवश्यक दिशा—निदेश निगत करना।
- 5. राज्य में राष्ट्रीय परिवार नियोजन इन्डीमनी योजना / क्षतिपूर्ति के भुगतान की समीक्षा।
- 6. राज्य स्तरीय कमेटी की प्रत्येक त्रैमास में एक बैठक का आयोजन किया जायेगा।
- 7. कमेटी की गणपूर्ति कम से कम 3/10 अनिवार्य होगी ।
- 8. कमेटी कार्यों के व्यवस्थित संचालन हेतु संयुक्त निदेशक या निदेशक स्तर अधिकारी नामित करेगी ।
- 9. जिला स्तरीय कमेटी त्रैमासिक सूचनायें निर्धारित प्रारूप पर राज्य स्तर कमेटी के समक्ष उपलब्ध करायेंगी ।
- 10.राज्य स्तरीय कमेटी जिलों से प्राप्त सूचना की प्रत्येक 6 माह में समीक्षा करेगी यदि किसी अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता हो तो प्राप्त करेंगी ।
- 11.राज्य स्तरीय कमेटी, जिला स्तरीय कमेटी पर निगरानी / नियंत्रण रखेंगी एवं आवश्यक दिशा—निर्देश प्रदान करेगी। यदि आवश्यक हुआ तो जिला स्तरीय सदस्यों हेतु समय—समय पर प्रशिक्षण का आयोजन भी करेंगी।

(एस.रामास्वामी) प्रमुख सचिव।

संख्या- 1383 (1)/XXVIII-4-2013-22/2008, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली ।
- 2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी / कुमाऊँ मण्डल नैनीताल ।
- 3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
- 4. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड ।
- 5. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 6. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल / नैनीताल, उत्तराखण्ड।
- 7. सम्बन्धित राज्य स्तर पर गठित क्वालिटी एश्यूरेन्स कमेटी के पदाधिकारी।
- -8. एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड शासन।
- 9. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से, (अतर सिंह) उप सचिव।